3332(E)
19/05/2026

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 18/05/2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत Widening and Strengthening work of Ashok Paper Mill to Bideshwarasthan Road (NH-57) via Fekla, Chikni from CH 0+00 to 11+335 Km. (Total Length-11.335 Km.) for the year 2025-26 कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक–2217(E) दिनांक–01.04.2026 एवं पत्रांक–2360(E) दिनांक–09.04.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री अनिल कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक–17.03.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक–943 दिनांक–17.03.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1340(अनु०) दिनांक–30.04.2026 के माध्यम से परिवाद पर दिनांक–30.04.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	Widening and Strengthening work of Ashok Paper Mill to Bideshwarasthan Road (NH-57) via Fekla, Chikni from CH 0+00 to 11+335 Km. (Total Length-11.335 Km.) for the year 2025-26
2.2	योजना मद	:	5054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, दरभंगा।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹5472.26 लाख। विभागीय ज्ञापांक–5068(एस०) दिनांक–22.08.2023
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹5148.25 लाख। मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–511(अनु०) दिनांक–02.12.2024
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹4811.33 लाख।
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	18 (Eighteen) Months (Including Monsoon Period)

2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	30.01.2026
2.10	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	पुनर्निविदा है। प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एक भी निविदाकार सफल नहीं हुए। पुनर्निविदा में सफल न्यूनतम निविदाकार द्वारा एकरारनामा नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा के कार्यालय आदेश–सह–पठित ज्ञापांक–51 दिनांक–07.01.2026 द्वारा पुनर्निविदा को रद्द करने के पश्चात् यह पुनर्निविदा आमंत्रित की गई।

3. विषयांकित पुनर्निविदा में निम्नलिखित 07 (सात) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) Raj Kishor Singh
(2) Narsingh Singh
(3) M/s Barhonia Engicon Pvt. Ltd.
(4) M/s Kailash Prasad Yadav Construction Pvt. Ltd.
(5) Maa Rajeshwari Construction Pvt. Ltd.
(6) Kamac Engineers Pvt. Ltd.

4. उपभागीय ज्ञापांक–943 दिनांक–17.03.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–17.03.2026 को तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही में उक्त पुनर्निविदा में छः निविदाकारों में से चार निविदाकार यथा (1) Raj Kishor Singh (2) M/S Barhonia Engicon Pvt. Ltd. (3) M/S Kailash Prasad Yadav Constructions Pvt. Ltd. एवं (4) Kamac Engineers Pvt. Ltd. द्वारा निविदा की वांछित अर्हत्ता को पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल एवं शेष दो निविदाकार यथा (1) Narsingh Singh को NIT के क्रमांक–29 एवं (2) Maa Rajeshwari Construction Pvt. Ltd. को SBD के ITB Cl.- 4.8 (Misleading and False representation) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया।

विभागीय निदेश के अनुसार दो कार्य दिवस में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही वित्तीय बीड खोलने हेतु निदेश दिया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक–943 दिनांक–17.03.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–17.03.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के संदर्भ में विषयांकित कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल निविदाकार Barhonia Engicon Pvt. Ltd. के पत्रांक–PAT/03/202, PAT/03/204 एवं PAT/03/211 दिनांक–19.03.2026 द्वारा पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल निविदाकार यथा (1) Raj Kishor Singh (2) Kamac Engineers Pvt. Ltd. एवं (3) M/s Kailash Prasad Yadav Constructions Pvt. Ltd. के विरूद्ध परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1340(अनु०) दिनांक–30.04.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक–30.04.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त निर्णय के विरूद्ध तकनीकी बीड में सफल निविदाकार Barhonia Engicon Pvt. Ltd. के पत्रांक–PAT/03/202, PAT/03/204 एवं PAT/03/211 दिनांक–19.03.2026 द्वारा परिवाद समर्पित किया गया है।

परिवाद की समीक्षा :–

परिवाद	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय/अनुशंसा	परिवाद समिति की अनुशंसा
Barhonia Engicon Pvt. Ltd. द्वारा प्राप्त परिवाद **(A) Rajkishor Singh के विरूद्ध दिया गया परिवाद :–** I would like to bring to your attention some observations regarding the tender. There are some shortcomings that tenderer has withheld that should make the tenderer Non-Responsive. 1. The tenderer was awarded the contract with BRPNNL-Construction of HL RCC Bridge (8 x 24.00M) in Chandani Chowk-Ajmatpur Mainpur Road in the district of Araria. However at 45.78% below, the agreement was never done. 2. The tenderer has gone to court against BRPNNL, Bihar against the work that it had bid. The court case is still pending. It needs to be checked whether the tender has shown these details in the tender document and whether the litigation history has been shown in the tender document. Please check above facts before proceeding to the financial evaluation process.	प्रबंध निदेशक, BRPNNL, Patna के पत्रांक–947 (अनु०) दिनांक–06.04.2026 से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अंकित विषयक कार्य के संबंध में निविदाकार द्वारा माननीय न्यायालय में Writ Petition दायर किया गया है, किन्तु निविदाकार द्वारा उक्त तथ्य Litigation History में अंकित नहीं किया गया है। अतः परिवाद का यह बिन्दु मान्य है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

(B) Kamac Engineers Pvt. Ltd. के विरूद्ध दिया गया परिवाद :– I would like to bring to Bring to your attention some observations regarding the tenderer. There are some shortcomings that tenderer has withheld that should make the tenderer Non-Responsive. **1.** The company has been debarred/blacklisted many times however this has not been declared in the tender document. a. Debarred in Water resources department, Bihar Bid was rejected in RWD previously- **2.** Kamac Engineers Pvt. Ltd. (Bid ID-586564) क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आधार पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इन्हें निविदा में भाग लेने से जल संसाधन विभाग के आदेश सं०–4245 दिनांक–13.10.2022 से DEBAR किये जाने के कारण SBD PMGSY-III की कंडिका–4.7 (ii) के अनुसार न्यूनतम अर्हत्ता पूरी नहीं हुई। अतः इन्हें तकनीकी बीड में अयोग्य घोषित किया जाता है।	निविदाकार के विरूद्ध जल संसाधन विभाग के आदेश, ज्ञापांक–4245, दिनांक–13.10.2022 से किये गये डिबार को उसी विभाग के विभागीय आदेश संख्या–3330 दिनांक–23.08.2024 से स्थगित किया जा चुका है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।
b. Blacklisted in RCD, Bihar. M/S Kamac Engineers Pvt. Ltd. (a) निविदाकार M/s Kamac Engineers Pvt. Ltd. को पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–6279(E) दिनांक 16.12.2024 तथा पत्रांक–4983(E) दिनांक–07.10.2024 के द्वारा 10 वर्षों के लिए कालीकृत किया गया, जिसका कालीकृत से संबंधित कोई कागजात संलग्न नहीं किया गया है, जिससे कालीकरण के	निविदाकार को पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–6279(E) दिनांक 16.12.2024 तथा पत्रांक–4983(E) दिनांक–07.10.2024 के विभागीय आदेश को क्रमशः पथ निर्माण विभाग के विभागीय आदेश, ज्ञापांक–7000(E) दिनांक–13.10.2025 एवं विभागीय आदेश, ज्ञापांक–6999 (E) दिनांक–13.10.2025 से निरस्त	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

मामले को समाप्त समझा जा सके।	किया जा चुका है। इसका उल्लेख शपथ पत्र में निविदाकार द्वारा भी किया गया है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।	
(b) इनके द्वारा निविदा में अपलोड किये गये कागजातों के साथ संलग्न Key Personnel Engineer के सभी शपथ पत्र 20 रूपये के Stamp पर है, जो कि शपथ पत्र 100 रूपये के Stamp पर होनी चाहिए तथा सभी शपथ पत्र में Welfare Ticket भी नहीं लगाया गया है, जो गलत प्रतीत होता है।	NIT के क्रमांक 25 के आलोक में निविदाकार द्वारा Key Personnel Engineer List से संबंधित Uploaded शपथ–पत्र समुचित Stamp Paper (Rs. 100/- Stamp+Rs.25/- Advocate welfare stamp) पर दिया गया है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।
(c) Debarred in NHIDCL- Sub: Four Laning of Jhanji to Demnow from Km, 491.050 to Km. 535.250 of NH-37 in the state of Assam under SARD on Engineering Procurement and Construction (EPC) Mode ORDER of DEBARMENT for a period of ONE YEAR from participating in the future projects of NHIDCL - Reg.	NHIDCL के पत्रांक–2430 दिनांक–19.05.2023 से निविदाकार को एक साल के लिए Debar किया गया है जो कि समाप्त हो चुका है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।
2. Existing commitment and Bid already submitted details have been withheld. Please find details of the company participating in West Bengal this details can be found on https://wbtenders.gov.in/nicgep/app	West Bengal Tenders Portal से स्पष्ट है कि निविदाकार द्वारा दिनांक–13.01.2026 को Tender ID:-2025_PRD_ 975201 _ 1, Tender Ref. No.- 66/ RIDFXXXI/ID/SE/RRNMU/ MALDA/2025-26 Its call में भाग लिये हैं एवं उक्त कार्य का वित्तीय बीड दिनांक– 02.02.2026 को खुला है। अतः निविदाकार दिनांक–02.02. 2026 तक उक्त निविदा की प्रतिस्पर्धा में थे, किन्तु इनके द्वारा Bid already Submitted में नहीं	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	दर्शाया गया है। अतः परिवाद का यह बिन्दु मान्य है।	
3. The contractor participated in BRPNNL however I'm not sure if this has been declared in the tender document. • Construction and improvement Bypass Road with 01 No ROB from Bhutaha More (NH-107 in Km-171) to Millia Polytechnic College (SH-60 in Km 4 Via Purnea-Srinagar Road from Ch.-0+000 to 9+176. km on Engineering, (Total Length-9.176 Km. on Engineering Procurement & Construction (EPC) Mode futur निर्माण कार्य। Please check above facts before proceeding to the financial evaluation process.	प्रबंधक निदेशक, BRPNNL के पत्रांक–946 (अनु0) दिनांक–06.04.2026 एवं वरीय परियोजना अभियंता BRPNNL, कटिहार का Email दिनांक–11.04.2026 से स्पष्ट है कि दिनांक–12.01.2026 (निविदा की तिथि 30.01.2026 के पूर्व) को परिवादित कार्य का Financial Bid Open हुआ एवं दूसरे संवेदक, Shree Khatu Shyam Developers को आवंटित हुआ। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।
(C) M/S Kailash Prasad Yadav Constructions Pvt. Ltd. के विरूद्ध दिया गया परिवाद :– Respectfully, I would like to point that the tenderer M/s Kailash Prasad Yadav Constructions Pvt. Ltd. has shortcoming in their tender submission that will make the tenderer non-responsive. 1. M/s Kailash Prasad Yadav Constructions Pvt. Ltd. has not submitted Power of Attorney (POA) on a valid stamp paper of Rs. 1000/- which should be publicly notarized (le. signed and witnessed by a state-appointed official who serves as an impartial witness). This is mandatory as per clause #26 of the NIT which states that 26. *As* per Prohibition, Excise & Registration Department, Bihar	ITB Cl 4.2 (iv) में अंकित है कि निविदाकार को "Power of Attorney, if any" के संबंध में Information देना है, के आलोक में निविदाकार द्वारा Board Resolution में विषयक निविदा के लिए अपने एक Director को प्राधिकृत किया गया है, जो मान्य है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।	SBD के ITB-Cl.4.2(iv) में Power of Attorney रहने की स्थिति में इसकी सूचना निविदा में देने का प्रावधान है अर्थात् निविदा में Power of Attorney देने की बाध्यता नहीं है। M/s Kailash Prasad Yadav Construction Pvt. Ltd. द्वारा निविदा में Board

Notification No.- 1026 Dt. 15.02.2013, it is mandatory that power of attorney, if applicable, should be on Rs. 1000/- stamp. The department has taken the decision of accept a Resolution instead of a POA based on "if applicable" phrase in the above mentioned clause #26 of NIT however this "if applicable" clause only applies to Proprietorship and not Partnership or private limited firms where there are more than one partners/directors and not at one's discretion, whether it is needed or not. A board resolution cannot replace the need of a POA due to following statutory acts - **a.** Failure to create legal agency [Indian Contract Act, 1872] (Law of Agency:- Under Section 182 and 186 of the Indian Contract Act. A Board Resolution is merely an "Inreation to Authorize" (Internal) whereas a Power of Attorney is the "Actual Authorization" (external). For a Private Limited Company, which is a distinct legal entity, the Indian Contract Act requires a formal creation of Agency . By failing to provide a 1000 stamped POA, the tenderer has failed to create a legally binding 'Agency,' making their bid a legal nullity. **b.** Indian Partnership Act, 1932 [for partnership firms] if the tenderer is a partnership firm, they cannot rely on "Implied Authority" Under section 19 (2) and 22 a single partner cannot bind the firm to contracts involving arbitration or		Resolution संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार कंपनी के एक Director को निविदा के लिये प्राधिकृत किया गया है। परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है। परिवाद समिति द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर सहमति प्रदान की जाती है।

relinquishments of claims without express authority. In a firm with multiple partners, a "resolution" or "letter" is not a legal instrument. A board resolution is a promise made by directors to themselves, whereas a POA is a promise and a formal instrument signed by the company to the world. **c.** Companies Act,2013 [Internal minutes vs Statutory instrument]- under the section 179 of the companies Act, it defines powers of board and 179(3) states that board of directors of company shall exercise the powers on behalf of the company by means of resolution passed at the meetings of the Board, provided that "the Board may, by a resolution passed at a meeting, delegate to any committee of directors, the managing director, the manager or any other principal officer of the company or in the case of a branch office of the company" it does not say that board resolution is legal instrument or it can act as a legal instrument substituting power of attorney. Board resolution mere internal permissions for the company not to the third party **d.** Bhartiya Sakshya Adhiniyam 2023, section 84, presumption as to power of attorney which states "The court shall presume that every document purporting to be a power of attorney and to have been executed before and authenticated by a Notary Public or any Court, Judge, Magistrate, Indian Counsel or Vice Counsel, or vice Counsel or representative of the central government was so		

executed and authenticated" Since the tenderer has not provided any such authenticated instrument the department has no legal basis to presume that the person signing the tender documents has the authority to do so. **e.** Indian Stamps Act 1899 Section 35, is the foundational "Tax Law" for legal documents in India. Under the Act, the "Stamp" isn't just a fee; it is a certificate of validity. Without it, a document is "destitute of legal effect" in a courtroom. The biggest reason litigation often requires a POA instead of just a Board Resolution comes down to Article 48 of the Indian Stamp Act. **f.** Power of Attorney (POA): Specifically listed in the Schedule of the Stamp Act. It must be stamped to be "duly executed." If it isn't, Section 35 kicks in, making the document inadmissible in evidence. **g.** Board Resolution: Generally considered an "internal minute" of a company. It is typically not listed as a chargeable "instrument" under the Stamp Act. **h.** The Conflict: If you try to use a Board Resolution to do the work of a POA, the court will view it as an unstamped POA in disguise. **i.** Section 35: The "Death Blow" to Litigants This is the most feared section for anyone in court. It states: "No instrument chargeable with duty shall be admitted in evidence, unless such instrument is duly stumped."		

j. If the department's authority to sue is based on an unstamped document: The judge cannot legally "see" the document and it will be impounded. Section 35 of the Indian Stamp Act, 1899, is the "gatekeeper" of the courtroom. **k.** It is a mandatory provision that prohibits any authority (like a judge or a registrar) from looking at, acting upon, or registering a document unless it is "duly stamped". **l.** Under Notification No. 1026 (2013) and the Indian Stamp Act, 1899, specifically set the 1,000 rate to ensure that POAs contribute to the state's revenue. Without this payment, the Registrar will simply reject the filing. A stamped document has a unique serial number and date, making it much harder for someone to backdate a fake authorization or "invent" a board resolution after a dispute has started or simply deny the commitment made on back of a board resolution. **m.** Paying stamp duty on a Power of Attorney (POA) in Bihar is not just about paying a fee - it is a mandatory legal requirement that transforms a private agreement into an officially recognized legal instrument. At its core, stamp duty is a tax levied by the state government. It is one of the primary ways states generate revenue from legal and commercial transactions occurring within their borders. Substituting a board resolution for a formal Power of Attorney results in a significant loss of statutory stamp duty		

and registration fees for the public treasury; making the department an accomplice to undermining tax compliances. **n.** Memorandum of Association (MOA)/Article of Association (AOA) forms the basis of engaging and defines the rules in the manner a private limited firm will engage beyond its boundaries; and it clearly mentions THE SEAL 32 The Company shall have common Seal and the Directors shall provide for the safe custody thereof. The seal shall not be applied to any instrument except by the authority of a resolution of the Board of Directors and in the presence of the Managing Director with one other Director authorized by the Managing Director and signing every instrument to which the seal has been affixed shall be conclusive evidence of the fact that the seal has been properly affixed. The bidder has violated its own Articles of Association (Clause 32), which mandates that an instrument has to be signed for it to be conclusive evidence and a resolution executed under the Common Seal in the presence of the Managing Director and one other Director, is a prerequisite. By submitting only a Resolution and not a formal Power of Attorney on a 1,000/- stamp (an instrument), the bidder has failed to provide 'conclusive evidence' of authority, rendering the bid Non-Responsive under RCD SBD Clause 4.2.		

Here is how this specific clause makes a Board Resolution alone insufficient and why the contractor's bid should be declared Non-Responsive: The "Instrument Rule (Legal Proof) - The clause states: "The seal shall not be applied to any instrument except by the authority of a resolution... and in the presence of the Managing Director with one other Director." • The Board Resolution is the "authority," but it is not the "instrument." • The Power of Attorney is the "instrument." • The Problem: If the contractor only submitted a Board Resolution, they have provided the permission to create an instrument but have not provided the instrument itself. The copy of Resolution dated 17th Day of January 2026 is vague, unspecific and without showing total strength of its directors and issuance of proper notices to all the directors prior to holding such meeting for business assigned under it ipso-facto will not entitle Sri Prakash Kumar to participate in the above referred NIT on behalf of M/s Kailash Prasad Yadav Constructions Pvt. Ltd. Patna. The department in the past has rejected bid if the bidder has only submitted. board resolution and not POA on Rs. 1000 /- stamp paper. The department has also rejected bid if bidder has submitted on Rs.100/- stamp paper, the content of the POA on 100/- being same as a board resolution. The Department's application		

of Clause 26 of the NIT has been manifestly arbitrary and lacks uniformity. The Department is engaging in 'pick-and-choose' tactics that violate the principles of natural justice and fair play in public procurement.		
ii. The tenderer is seen to be working on multiple projects in North Bihar Power Distribution Corporation Limited and payment has been made in December 2025 by the Electrical Superintending Engineer, Electric Supply Circle Saharsha. The audited balance sheet of 2023-24, which is a publically available document for private limited company, we can see that the company received a payment of 1.89 Crores from NBPDCL. For FY 24-25, the payment received has been shown as 1.09 Crore. However this has been withheld from the tender document. Kindly verify from the department about the existing and ongoing project. The tender papers submitted by M/s Kailash Prasad Yadav Constructions Pvt. Ltd. are non- responsive under RCD SBD Clause 4.2. I earnestly request that their bid be declared unfit and disqualified before the opening of financial bids. Kind regards.	अधीक्षण अभियंता, Electric Supply Circle, Saharsa के पत्रांक–444 दिनांक–30.03.2026 एवं पत्रांक–570 दिनांक–22.04.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्त्तमान में निविदाकार के पास उनके अधीन किसी भी प्रमंडल में कोई कार्य लंबित नहीं है। अतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

7. <u>परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :–</u>

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक–17.03.2026 को लिये गये निर्णय को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए छः निविदाकारों में से दो निविदाकार (1) M/S Barhonia Engicon Pvt. Ltd. एवं (2) Kailash Prasad Yadav Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में सफल तथा शेष चार निविदाकार यथा (1) Narsingh Singh को NIT के क्रमांक–29 के आलोक में (2) Maa Rajeshwari Construction Pvt. Ltd. को SBD के ITB Cl.- 4.1 Section-2 (Qualification information) की कंडिका–1.4 (A) के आलोक में (3) Raj Kishor Singh को SBD के ITB Cl.- 4.1 Section-2 (Qualification information) की कंडिका–1.11 के आलोक में एवं (4) Kamac Engineers Pvt. Ltd. को SBD के ITB Cl.- 4.1 Section-2 (Qualification information) की कंडिका–1.4 (B) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा करती है।

8. परिवाद समिति का निर्णय :–

(i) विषयांकित कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल निविदाकार **Barhonia Engicon Pvt. Ltd.** के पत्रांक–**PAT/03/202, PAT/03/204** एवं **PAT/03/211** दिनांक–**19.03.2026** द्वारा पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में सफल निविदाकार यथा (1) **Raj Kishor Singh** (2) **Kamac Engineers Pvt. Ltd.** के विरूद्ध दिए गए परिवाद/आपत्ति को मान्य किया जाता है एवं (3) **M/s Kailash Prasad Yadav Constructions Pvt. Ltd.** के विरूद्ध दिए गए परिवाद/आपत्ति को अमान्य किया जाता है।

(ii) चार निविदाकार यथा (1) **Narsingh Singh** को NIT के क्रमांक–29 के आलोक में (2) **Maa Rajeshwari Construction Pvt. Ltd.** को SBD के ITB Cl.- 4.1 Section-2 (Qualification information) की कंडिका–1.4 (A) के आलोक में (3) **Raj Kishor Singh** को SBD के ITB Cl.-4.1 Section-2 (Qualification information) की कंडिका–1.11 के आलोक में एवं (4) **Kamac Engineers Pvt. Ltd.** को SBD के ITB Cl.- 4.1 Section-2 (Qualification information) की कंडिका–1.4 (B) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित किया जाता हैं।

(iii) दो निविदाकार यथा (1) **M/S Barhonia Engicon Pvt. Ltd.** एवं (2) **Kailash Prasad Yadav Construction Pvt. Ltd.** को तकनीकी बीड में सफल घोषित किया जाता है। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है।

(iv) उपभागीय ज्ञापांक–943 दिनांक–17.03.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–17.03.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(v) मुख्य अभियंता, उत्तर संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

8.2 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

(सुनील कुमार सुमन)	(राजेश कुमार गुप्ता)	(अनिल कुमार सिंह)	(उमा कान्त रजक)
मुख्य अभियंता,	मुख्य अभियंता, संविदा	अभियंता प्रमुख	अभियंता प्रमुख–सह–अपर
उत्तर, पथ निर्माण विभाग,	प्रबंधन, नीतिगत मामले	(मुख्यालय),	आयुक्त–सह–विशेष सचिव
बिहार, पटना।	एवं लेखा परीक्षा,	पथ निर्माण विभाग,	(कार्य प्रबंधन),
	पथ निर्माण विभाग,	बिहार, पटना।	पथ निर्माण विभाग,
	बिहार, पटना।		बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0–7/निविदा–03–32/2026 3332 (E) पटना, दिनांक 19/05/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।